भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या995

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

माओवादी-रोधी योजना के अंतर्गत और अधिक जिलों को लाया जाना

995. श्री रीताब्रता बनर्जीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार माओवादी-रोधी योजना के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को लागू करने तथा जन-अवबोधन प्रबंधन के क्षेत्रों में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से राज्य सरकारें विशिष्ट रुप से निपटती हैं। केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की गहनता से निगरानी करती है तथा सुरक्षा एवं विकास, दोनों मोर्चों पर विविध प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करती है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जिलों को शामिल करना/हटाया जाना, वहां हिंसा की स्थिति पर आधारित होता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसकी कोई समय-सीमा नहीं है।